

बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद राहुल की न्याय यात्रा प्रभावित

पटना (हिंस)। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद लालू यादव की पार्टी राजद को जोर का झटका लगा है। साथ ही कांग्रेस की भारत जोड़ा न्याय यात्रा पर भी इसका खासा असर पड़ा है। पूर्णिया में राहुल गांधी के साथ एक मंच पर लालू यादव और तेजस्वी यादव के नहीं होने से कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। राहुल बिहार में अपने सहयोगी दलों के साथ जो ताकत दिखाना चाहते थे, वैसा कुछ भी वे नहीं कर पाए हैं। बिहार में अपनी मजबूत ताकत दिखाने के लिए कांग्रेस की ओर से भारत जोड़े न्याय यात्रा किंशनगंज के रास्ते बिहार में प्रवेश कर चुकी है। उम्मीद थी कि 30 जनवरी को पूर्णिया में होने वाली राहुल गांधी की जनसभा में कांग्रेस अपने सहयोगी दलों को एक मंच पर लाकर एकजुटता का संदेश देगी लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव को नौकरी के बदले जयीन घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी द्वारा बुलाने से कांग्रेस और राहुल गांधी को झटका लगा है। राहुल गांधी की पूर्णिया जनसभा में कांग्रेस अपनी ताकत दिखाना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस ने पिछले करीब 15 दिनों से बड़ी तैयारी की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने आईएनडीआई गठबंधन के घटक दलों को भी आमंत्रित किया था। इसमें लालू यादव और तेजस्वी यादव भी शामिल थे। उम्मीद थी कि लालू और तेजस्वी के पूर्णिया में राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने से भरी भीड़ जुटती। इतना ही नहीं राहुल, लालू और तेजस्वी के एक साथ मंच पर आने से कांग्रेस और राजद की एकजुटता का भी परिवृद्धश दिखता लेकिन ईडी की पूछताछ ने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

पीएम मोदी नेतृत्व में आम कार्यकर्ता भी बन सकता है मुख्यमंत्री : बिप्लब देब
प्रदेश प्रभारी ने फरीदाबाद में किया बीजेपी लोकसभा सीट के कार्यालय का उद्घाटन

फरादाबाद (हस्म)। हारयाणा में भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों का शंखनाद कर दिया है। मंगलवार को प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर पार्टी ने अपने कार्यालय खोले। इनका उद्घाटन प्रदेश प्रभारीराज बिप्लब कमार देव ने फरोदाबाद में किया।



मुझना चाहता है। हम सभी को अध्यक्ष नहीं बना सकते। जब तक मोदी के नेतृत्व में सरकार है, तब तक एक आम कायकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन, कांग्रेस में

— २४ —

उप्र में आठ जिलों के जिलाधिकारी समेत कई आईएएस का तबादला

लखनऊ (हिम्म)। राज्य सरकार ने सोमवार बीती रात को उत्तर प्रदेश में 19 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसमें कई जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासनिक अधिकारियों में तबादले का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में सोमवार की देर रात को शासन ने कानपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, रामपुर, अमेठी सहित कई जिलों के जिलाधिकारी समेत कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। कानपुर के जिलाधिकारी विशाख जी को अलीगढ़ का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। वह काफी समय से यहां पर तैनात थे। उनकी जगह पर गाजियाबाद के जिलाधिकारी आरके सिंह को इसी पद पर कानपुर भेजा गया है। बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह को पीलीभीत का जिलाधिकारी, अलीगढ़ के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह को गाजियाबाद जिलाधिकारी, फरुखाबाद के जिलाधिकारी संजय कुमार

प्रथम को रामपुर भेजा गया है। इसी तरह रामपुर के लालिधकारी रविंद्र कुमार मंदर को जौनपुर का लालिधकारी बनाया गया है। जौनपुर के जिलाधिकारी नुज झा को एसीईओ राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया। श्रम विभाग में तैनात निशा आनंद डीएम अमेठी गायी गयीं हैं। राज्य संपत्ति अधिकारी वोके सिंह लालिधकारी फर्स्टखाबाद बनाए गए हैं। गाजियाबाद और जौनपुर के जिलाधिकारी को चुनाव आयोग में तैनाती के न साल की अवधि के मानक के तहत वहाँ से स्थानांतरण या गया है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि वापसन विभाग के विशेष सचिव दिव्यांशु पटेल को गोदाबाद का नगर आयुक्त और आगरा के मुख्य विकास अधिकारी मनिकनंदन ए को बरेली विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा कई आईएएस तबादले इधर-उधर विभाग में किए गए हैं।

सरकार ने शव को सड़क पर प्रदर्शन करने पर लगाया

चंडीगढ़ (हम)। हारियाणा में अब काइ भा व्याकृत शरखकर प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। हारियाणा सरकार ने मंगलवार की बैठक में डेड-बॉडी (मृत शरीर) के अधिकार और गरिमा के लिए एक महत्वपूर्ण नियंत्रण लिया। इस बैठक में द ह डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल, 2024 को मंजूरी दी गई। उद्देश्य किसी मृत शरीर का सभ्य और समय पर अंतिम संस्कार में बाधा डालने वाले किसी भी अनुचित विरोध रोकने की आवश्यकता को पहचानते हुए, यह विधेयक स्पष्ट निपटान के संबंध में किसी भी मांग या प्रदर्शन पर रोक लगाएगा। कानून उन मामलों में सार्वजनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है जहां परिवार के सदस्य मृत शरीर को अस्थीकार कर देते हैं। अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में को को करदम उठाने और मृत शरीर के लिए गरिमापूर्ण और अंतिम अनुचित विरोध का लाभ लिया जाता है।

अखिल भारत हिंदू महासभा ने गांधीजी की पुण्यतिथि पर मनाया शौर्य दिवस



मेरठ (हिंस)। अखिल भारत हिंदू महासभा ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मंगलवार को सौर्य दिवस मनाया । इस दौरान महासभा के कार्यालय पर हवन पूजन, अनुष्ठान किया और हनुमान चार्चा का आयोजन किया ।

चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव में भाजपा
ने इंडी गठबंधन को दी करारी मात

नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर पर भाजपा का कब्जा
चंडीगढ़ (हिंस)। चंडीगढ़ नगर निगम के प्रतिष्ठित चुनाव में विपक्ष के आईएनडीआईए (इंडी गठबंधन) को भारतीय जनता पार्टी ने करारी मात्र दी है। भाजपा ने नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद पर कब्जा कर लिया है। मतगणना में चुनाव अधिकारी की ओर से विपक्षी गठबंधन के आठ वोटों को अमान्य कर देने पर आम आदमी पार्टी तथा कांग्रेस ने हाई कोर्ट में दस्तक दी है। कई दिनों की राजनीतिक उठापटक और सियासी घमासान के बीच भाजपा के मनोज सोनकर ने विपक्ष के इंडी गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप टीटा को चार वोटों से हरा दिया। मेयर पद के लिए 35 पार्षदों ने वोट डाला। जिनमें से भाजपा के मनोज सोनकर को 16 तथा आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार को 12 वोट मिले। मतगणना में चुनाव अधिकारी ने इंडी गठबंधन की आठ वोटों को अमान्य कर दिया। मंगलवार को मेयर पद के चुनाव के बाद सदन में काफी देर तक हंगामा होता रहा। कांग्रेस व आप पार्षदों ने सदन से बहिष्कार कर दिया। इसके बाद सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव में विपक्षी पार्षदों ने भाग नहीं लिया और भाजपा के कुलजीत सिंह को इस चुनाव में 16 वोट मिले और वह सीनियर डिप्टी मेयर चुन लिए गए। इसके बाद हुए डिप्टी मेयर चुनाव में भी भाजपा उम्मीदवार राजिंदर शर्मा जीत गए। चुनाव प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए आम आदमी पार्टी तथा कांग्रेस ने फिर से हाई कोर्ट में दस्तक दी है। दोनों दलों ने याचिका दायर करके चुनाव प्रक्रिया स्थगित करने की मांग की है। चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके समझौते को बहाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा चंडीगढ़ यूनिट को लंबे समय से मेयर चुनाव का इंतजार था। वह इस जीत के लिए चंडीगढ़ यूनिट को बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चंडीगढ़ में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन को मिली हार ने साफ कर दिया है कि लोग काम में विश्वास करते हैं, न की छल-कपट की राजनीति को पसंद करते हैं। दूसरी तरफ आप सुरीमो एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केरियाल ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिनदहाड़े जिस तरह से बैद्यमानी की गई है, वो बेहद चिंताजनक है। यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह बेहद चिंताजनक है।

करके समूची लीडरशिप को
कहा कि भाजपा चंडीगढ़ यूनिट
से मेयर चुनाव का इंतजार था।
लिए चंडीगढ़ यूनिट को बधाई
नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चंडी
विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने
गठबंधन को मिली हार ने सारा
लोग काम में विश्वास करते
कपट की राजनीति को पसंद
तरफ आप सुप्रीमो एवं दिल
अरविंद के जरीवाल ने कहा
चुनाव में दिनदहाड़े जिस तर
गई है, वो बेहद चिंताजनक है।
चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं कि ये किसी भी हाद
यह बेहद चिंताजनक है।

शिक्षण संस्थानों में सभी के लिए हो समान यूनिफॉर्म : विश्व हिंदू परिषद

जयपुर (हिंस)। राजस्थान के स्कूलों में ड्रेस कोड या बुर्का-हिजाब पहनने के विवाद पर विश्व हिंदू परिषद ने समान गणवेश का समर्थन किया है। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय ने कहा कि अनुशासन के लिए सभी शिक्षण संस्थानों में समान गणवेश अनिवार्य होना चाहिए। विद्यालयों में गणवेश का उद्देश्य है कि सभी छात्रों के मन में समता का भाव हो तथा वेशभूषा के कारण सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या अन्य किसी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न न हो। उन्होंने उच्च न्यायालय कर्नाटक के निर्णय का उदाहरण देते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य भाग न होकर स्वेच्छा पर निर्भर है। रामगंज में हुए विवाद पर उन्होंने कहा कि स्कूल की छोटी छात्राएँ इस प्रकार के आंदोलन को अंजाम देने में सक्षम नहीं हैं। देश के आपसी सौहार्द को बिगड़ने के लिए अलगववादी सोच रखने वाले कुछ लोग बच्चियों को मोहरा बनाकर सड़क पर प्रदर्शन करता रहे हैं तथा प्रदेश में शारीर भंग करने का घटयंत्र कर रहे हैं जिनपर राज्य सरकार तथा प्रशासन द्वारा कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद क्षेत्रीय मंत्री ने प्रदेश और देश में चल रहे लैंड जिहाद पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आज कई स्थलों पर वक्फ बोर्ड ने अनैतिक रूप से कब्जा कर लिया है। मेवात जिले के 90 से ज्यादा गांव आज हिंदू विहान हो गए हैं और साइबर क्राइम का गढ़ बन चुके हैं। इन गांव में गौ तस्करी, ड्रास एवं अन्य साइबर क्राइम को छोटे-छोटे बच्चे भी अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी केंद्र और राज्य सरकार से मांग है कि देश में एक ही कानून के अनुसार काम हो और समान रूप से सब उसकी पालना करें।

धायक ने दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात कर की विकास योजनाओं पर चर्चा

अररिया (हिंस)। फारबिसगंज विधायक विद्यासागर
तेजाली ते संगतवारा तो मरेवा तो तोमें या, मालवारी माला



विकास कार्यों को गति मिलेगी और राज्यवासियों की बेहतरी होगी। उन्होंने कहा फारबिसगंज अम्हारा मुरब्लला सड़क मार्ग का जल्द ही शिलान्यास किया जाएगा और इस सड़क का निर्माण कार्य सुरु होगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के पूरब के इलाके के लोगों का वर्षों पुरानी मांग पूरी होने वाली है।

जम्मू और कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने घोषणापत्र समिति का किया गठन

जम्मू (हिंस)। जम्मू और कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष विलक्षण सिंह ने मंगलवार को घोषणापत्र समिति का गठन करके भविष्य के लिए पार्टी के दृष्टिकोण को आकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समिति आगामी संसदीय चुनावों के लिए पार्टी के घोषणापत्र को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बलवान सिंह (राज्य महासचिव) घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति में दो उप-समितियां होंगी जिनमें एक जम्मू प्रांत के लिए और दूसरी कश्मीर प्रांत के लिए। पार्टी की घोषणापत्र समिति में निम्नलिखित दो उप-समितियां शामिल होंगी। जम्मू प्रांत के लिए उप-समिति में नेरश चिब (राज्य महासचिव), राजेश गांधी (राज्य महासचिव), रविंदर जामवाल (राज्य सचिव) और शाम गोरखा (प्रांतीय अध्यक्ष जम्मू) जबकि कश्मीर प्रांत के लिए उप-समिति में एडवोकेट इश्फाक अहमद खान (राज्य उपाध्यक्ष), हकीम आरिक अली (राज्य सचिव), जहांगीर अहमद खान (राज्य सचिव) और फारूक अहमद डार (प्रांतीय अध्यक्ष जम्मू) शामिल होंगे। एक व्यापक और समावेशी घोषणापत्र सुनिश्चित करने के प्रयास में जो घटकों की विविध आवश्यकताओं और चिंताओं को संबोधित करता हो घोषणापत्र समिति पूरे क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ जुड़ेगी। समिति का उद्देश्य समाज के व्यापक स्पेक्ट्रम से अंतर्दृष्टि, राय और सिफारिशें एकत्र करना है ताकि एक ऐसा दस्तावेज बनाया जा सके जो वास्तव में लोगों की आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं को दर्शाता हो। विलक्षण सिंह ने पार्टी के एजेंडे को आकार देने में समावेशी दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया। विलक्षण सिंह ने कहा कि घोषणापत्र समिति पार्टी और समुदाय के बीच एक सेतु का काम करेगी जिससे यह सुनिश्चित होगा कि लोगों की चिंताएं और अपेक्षाएं हमारे चुनावी वादों में सबसे आगे हों। समिति विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और अन्य जैसे प्रमुख मुद्दों पर इनपुट एकत्र करने के लिए सामाजिक संगठनों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित करेगी। ये बात चीत पार्टी के घोषणापत्र को अंतिम रूप देने का आधार बनेगी। जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी पारदर्शिता, जवाबदेही और भागीदारीपूर्ण शासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। घोषणापत्र समिति का गठन लोगों की जरूरतों के प्रति समावेशीता और जवाबदेही के पार्टी के मूल मूल्यों के अनुरूप है। समिति द्वारा इस महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने के साथ ही जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी सभी संबंधित हितधारकों को सक्रिय रूप से भाग लेने और प्रक्रिया में योगदान देने के लिए आमत्रित करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अंतिम घोषणापत्र वास्तव में लोगों की सामूहिक इच्छा और दृष्टिकोण को दर्शाता है।

ग्रामीण ओलंपिक खेलों में यदि भ्रष्टाचार हुआ शिक्षक की शिकायत से है तो इसकी जांच करवाई जाएगी : खेल मंत्री आहत छात्र ने की आत्महत्या

जयपुर(हिंस)। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में केवल टी-शर्ट इत्यादि की खरीद पर हुए व्यय में यदि कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो राज्य सरकार वित्त विभाग के माध्यम से इसकी पूरी जांच कराएगी। कर्नल राठौड़ प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि यह गंभीर चिन्ता का विषय है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय 126 करोड़ रुपए की राशि इनकी खरीद पर व्यय कर दी गई। उन्होंने कहा कि खेल विभाग के बजट से भी 4 गुना अधिक व्यय किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए विधायक मनोज कुमार के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खेल मंत्री ने बताया कि प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल-2022 में 40 करोड़ 92 लाख 56 हजार 890 रुपए की राशि व्यय हुई। इसी प्रकार राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल- 2023 में 155 करोड़ 46 लाख 72 हजार 500 रुपए की राशि व्यय हुई। राठौड़ ने बताया कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए विधायक मनोज कुमार के लिए प्रतिभाओं के लिए प्रतिभाओं के चयन या सरकारी सेवा में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान नहीं है। कर्नल राठौड़ ने बताया कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हुए व्यय की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि विधायक की मांग को देखते हुए ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हुए व्यय की जांच करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान नियम के तहत 7 हजार 145 आवेदन प्राप्त हुए, जिनकी समीक्षा व प्रमाणीकरण पश्चात पात्र खिलाड़ियों को देय राशि का निर्धारण होगा। उन्होंने बताया कि आउट ऑफ टर्न सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए 142 विधायिकों ने आवेदन दर्शाया है।

राजभवन, मुख्यमंत्री आवास
और ईडी ऑफिस के 100 मीटर
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज कल से

